



सपादकोय

कठघरे में है सरकार

अगर लगे आरोपों को साक्ष्यों के जरिए साबित कर दिया जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना की छवि आजाद भारत में हुए एक बड़े राजनीतिक घोटाले के रूप में बनेगी। क्या इस प्रकरण की विशेष एवं पूरी जांच जरूरी नहीं है? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स के मुद्दे ने भारतीय लोकतंत्र की साख पर ऐसा ग्रहण लगाया है, जिसकी छाया से उबरना आसान नहीं होगा। अब यह बात बेहिचक कही जा सकती है कि चुनावी चंदे की यह योजना शुरूआत से ही बदनीयती से प्रेरित थी। मकसद चुनावी चंदे पर मोटा परदा डालना था। वैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय स्टेट बैंक ने जो जानकारियां सौंपी हैं, उससे बात सिर्फ यहीं तक नहीं रह गई है। बल्कि उससे कई बुनियादी सवाल उठे हैं। जब तक इन प्रश्नों पर स्थिति स्पष्ट नहीं होती, यह धारणा पुख्ता बनी रहेगी कि स्वार्थी और अवाञ्छित ताकतें धन-बल के जरिए सत्ताधारी दलों एवं राजनेताओं को साध कर अपना उल्लं सीधा कर रही हैं। सबसे परेशानी वाली बात यह सामने आई है कि कथित खोखा (शेल) कंपनियां सियासी चंदा दे रही हैं और पार्टीयां उन्हें स्वीकार भी कर रही हैं। कई ऐसी कंपनियां बेनकाब हुई हैं, जिन्हें एक वित्त वर्ष में जितना मुनाफा हुआ, उससे छह गुना से भी ज्यादा रकम उन्होंने चंदा दिया। तो सवाल उठा है क्या सियासी चंदा देने के लिए ही कुछ बड़े कॉर्पोरेट भरानों ने ऐसी कंपनियां बनाई? यह पहलू इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इनमें से कई कंपनियों की स्थापना इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना लागू होने के बाद हुई। एक अन्य मुद्दा चंदे के बदले लाभ पहुंचाए जाने और भयादेहन के बदले चंदा उगाहने के आरोप से संबंधित है। चूंकि स्टेट बैंक ने अभी तक यूनिक कोड उपलब्ध नहीं करवाए हैं, इसलिए ठोस रूप से यह दिखा पाना अभी संभव नहीं है कि किस कंपनी ने कब किस पार्टी को कितना चंदा दिया। मगर आकलन के आधार पर विशेषज्ञों ने इस तरफ इशारा किया है कि ईडी जैसी कंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के शुरू होने तुरंत बात कुछ कंपनियों ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदे। उधर कुछ कंपनियों को इस माध्यम से चंदा देने के कुछ समय बाद परियोजनाओं के बड़े ठेके मिले। अगर यह रिपोर्ट साक्ष्यों के साथ स्थापित कर दिया जाता है, तो फिर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड योजना की छवि आजाद भारत में हुए एक बड़े राजनीतिक घोटाले के रूप में बनेगी। क्या इस प्रकरण की पूरी जांच जरूरी नहीं है?

विचार

मैराथन चुनाव कार्यक्रम

चुनाव कार्यक्रम को देखकर अगर मैराथन दौड़ की याद आती हो, यह कहा जाएगा कि इसमें अंत तक टिके रहने के लिए आर्थिक संसाधन, टिकाऊ चुनाव मशीनरी और अपने चुनावी नैरेटिव को आकर्षक बनाए रखने की क्षमता पूर्व शर्त बन जाती हैं लोकसभा के आम चुनाव के कार्यक्रम की खबर एक विदेशी अखबार ने इस शीर्षक के साथ प्रकाशित की है- भारत में मैराथन चुनाव कार्यक्रम का एलान। एथलेटिक्स की दुनिया में कहा जाता है कि मैराथन दौड़ में शामिल होने के लिए सार्वांगिक बल, अंतर्राष्ट्रीय, टिकाऊ ऊर्जा एवं गहरे धीरज की जरूरत होती है। जिन धावकों में ये गुण ना हों, वे 42.195 किलोमीटर की इस प्रतिस्पर्धा में सफल नहीं हो सकते। भारत के चुनाव कार्यक्रम को देखकर अगर इस दौड़ की याद आती हो, यह भी सहज ही कहा जाएगा कि इसमें अंत तक टिके रहने के लिए कई खास पहलू अनिवार्य हो जाते हैं। आर्थिक संसाधन, लंबे समय तक सक्रिय रह सकने वाली चुनाव मशीनरी और अपने चुनावी नैरेटिव को आकर्षक बनाए रखने की क्षमता इनमें शामिल हैं। चुनावी चंदे और प्रचार तंत्र की वर्तमान स्थिति देखें, तो कहा जाएगा कि इन तकाजों को पूरा करना विपक्षी दलों के लिए एक कठिन चुनौती है। वैसे तो सात चरणों में लोकसभा का चुनाव होना अब नई बात नहीं रही, लेकिन इस बार एक खास पहलू यह है कि अनेक बड़े राज्यों में भी चुनाव को सात चरणों तक खींच दिया गया है। इससे यह कहने की स्थिति बनती है कि मैरें शुरू होने के पहले ही पिछ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल हो गई है। चूंकि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सातों चरणों में वोट डाले जाएंगे, इसलिए वहाँ हर मतदान के दिन करीब के चुनाव क्षेत्रों में प्रचार करने की गुंजाइश बनी रहेगी। वर्तमान रुझान यह है कि प्रधानमंत्री के भाषणों का टीवी चैनल सीधा प्रसारण करते हैं इस तरह मतदान के समय भी उनका संदेश मतदाताओं तक पहुंचता रहेगा। मतलब यह कि ऐसे चुनाव कार्यक्रम के कारण प्रचार संबंधी आदर्श चुनाव आचार संहिता बेमायने हो गई है। फिर मतदान के बाद 40 दिन तक वोटिंग मरीजों की विश्वसनीय ढंग से रक्षा और सुरक्षा की कठिन चुनौती बनी रहेगी। जिस समय चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई तरह के संदेह वातावरण में हैं, कहा जा सकता है कि ऐसे चुनाव कार्यक्रम से उन्हें दूर करने में कोई मदद नहीं मिलने वाली है।

चंदा सत्ता की पार्टी को ही !

चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को मिले चंदे का ब्योरा सार्वजनिक हो गया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने का जो कानूनी तरीका स्थापित किया गया था उसमें पारदर्शिता की कोई गुंजाइश नहीं थी। देश के नागरिकों से यह बात छिपाई गई कि किस पार्टी को कौन चंदा दे रहा है और कितना चंदा दे रहा है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस गोपनीयता पर से परदा हटा दिया है। यह भी कह सकते हैं कि पहला परदा हट गया है। यह पता चल गया है कि किस कंपनी ने किस तारीख को कितने रुपए का बॉन्ड खरीदा। यह भी पता चला है कि किस पार्टी ने किस तारीख को कितने रुपए का बॉन्ड भुनाया। हालांकि अब भी बॉन्ड का यूनिक नंबर सार्वजनिक नहीं किया गया है, जिससे यह पता चले कि किस कंपनी द्वारा खरीदा गया बॉन्ड किस राजनीतिक दल ने भुनाया है। फिर भी यह पता चल गया है कि किस कंपनी ने सबसे ज्यादा बॉन्ड खरीदा और किस पार्टी ने सबसे ज्यादा बॉन्ड को कैश कराया। अभी जितना खुलासा हुआ है उसका लब्बोलुआब है कि भले इसे राजनीतिक चंदे का नाम दिया जा रहा है लेकिन वह चंदा राजनीतिक दलों को कम और सरकारों को ज्यादा मिलता है। कहने का मतलब है कि जिस पार्टी की सरकार रहती है उसको चंदा मिलता है। विपक्षी पार्टियों को चिड़िया के चुग्गे के बराबर चंदा मिलता है। दूसरा निष्कर्ष यह भी है कि उत्तर भारत के हिंदी पट्टी की पार्टियों की हैसियत कुछ नहीं है। देश के बड़े कॉरपोरेट घराने उनको कुछ नहीं समझते हैं। इसका कारण यह भी हो सकता है कि हिंदी पट्टी के राज्यों में बड़े कॉरपोरेट घरानों के लिए कोई अवसर नहीं होता है इसलिए वे इस इलाके की पार्टियों को नाममात्र का चंदा देते हैं या नहीं देते हैं। तभी बिहार में सत्ता में होने के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को बहुत मामूली चंदा मिला है। उनके मुकाबले मुख्य विपक्षी राजद की थोड़ा ज्यादा चंदा मिलता है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी को भी चुनावी बॉन्ड के जरिए बहुत कम फॉर्डिंग हुई है, जबकि बसपा को चुनावी बॉन्ड से कोई चंदा नहीं मिला है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खनिज संपदा से संपन्न राज्य झारखण्ड में सत्तारूढ़ झारखण्ड मुक्ति मोर्चा चार साल से सरकार में है लेकिन उसका नाम टॉप पार्टियों में नहीं है।

क्या सैनी से भाजपा के हित सधेगें?

अजीत द्विवेदी

नायब सिंह संसा का हारियाणा का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भाजपा का नायब दांव माना जा रहा है। माना जा रहा है कि एक दांव से भाजपा ने कई लक्ष्य साध लिए हैं। अब भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इन्कम्वेसी तंत्र हो जाएगी। किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी। छठी जातियों का पूरी तरह से धर्वीकरण भाजपा के द्वारा ऐसे में हो जाएगा और दूसरी ओर त्रिकोणात्मक लडाई दुश्यंत चौटाला जाट वोटों का बटवारा करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हो सकता है कि उनका गोपनीयता क्या राजनीति सचमुच इस तरह एकरेखीय हो जाएगा? क्या राजनीति बदल जाएगी? क्या इन्हीं ही सरल होती है कि चुनाव से पहले एक बदल हार बदल देने से पूरी राजनीति बदल जाएगी? कुछ जन्मों जैसे गुजरात और उत्तराखण्ड में ऐसा जरूर हुई है कि उन राज्यों की राजनीति और सामाजिक संरचनाएँ नहीं बिन्दु थे। हारियाणा की राजनीति उनसे अलग है और उसी तरह जैसे कर्नाटक की राजनीति अलग थी और उसी हांह के चेहरा बदलने का दांव नहीं चला। हालांकि इसका असर है कि अलग अलग रूप से विफल ही हो जाएगा। बहराहल, बोटाला बालू बदला बालू आगे आधिक प्राप्ति की जाएगी।



पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए या नकली गोलियों से फायरिंग हुई उससे किसान नाराज हैं। उनकी नाराजगी निश्चित रूप से सिर्फ मनोहर लाल से नहीं होगी। भाजपा पिछले करीब 10 साल से हरियाणा में जट बनाम गैर जट की राजनीति करती रही है। उसने 10 साल पहले हरियाणा सहित कई राज्यों में शक्तिशाली और सत्ता की स्वाभाविक दावेदार मानी जाने वाली जातियों को छोड़ कर दूसरी जातियों को सत्ता सौंपी। महाराष्ट्र में गैर मराठा देवेंद्र फड़नवीस, हरियाणा में गैर जट मनोहर लाल खट्टर और झारखण्ड में गैर आदिवासी रघुबर दास मुख्यमंत्री बनाए गए थे। मोटे तौर पर यह राजनीति कामयाब रही है। हालांकि महाराष्ट्र और झारखण्ड में लगातार दूसरी बार सरकार नहीं बनी फिर भी भाजपा अपना बोट बढ़ाने और उसे बनाए रखने में कामयाब रही। इसी राजनीति के तहत पंजाबी समुदाय के मनोहर लाल को हटा कर पिछड़ी जाति के नायब सिंह सैनी सीएम बनाए गए हैं। गैर जट चेहरा बता कर उनको नायब दांव की तरह पेश किया जा रहा है। यह सही है कि राज्य में एक तिहाई से ज्यादा आबादी पिछड़ी जातियों की है लेकिन क्या सैनी के नाम से सब भाजपा से जुड़ जाएंगे? दूसरा सवाल यह है कि गैर

मछड़ी जातियों का क्या होगा? क्या वे भी सैनी के तामन कर भाजपा के इस प्रयोग को सफल बना देंगे? यह ध्यान रखने की जरूरत है कि सैनी अगर गैर जाट चेहरा हैं तो वे गैर ब्राह्मण भी हैं, गैर दलित भी हैं, गैर गुर्जर भी हैं तो फिर ये जातियां कैसे उनके साथ लड़ेंगी? क्या गैर जाट की भावना इतनी प्रबल है कि उसके विरोध में सारी जातियों किसी को भी नेतृत्वीकार कर लेंगी? अगर बहुत सरल तरीके से यह बतानें कि जिस जाति या समुदाय का व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है उसकी जाति उसके साथ ज्यादा मजबूती से लोलबंद होती है तो फिर इसी तर्क से यह मानना होगा कि दूसरी जातियां उससे दूरी बनाएंगी। इसलिए जातियां हिसाब कभी भी इतने सरल तरीके से काम नहीं करती हैं। उसके साथ कुछ और फैक्टर जोड़ने होते हैं जोनी के प्रयोग के साथ भाजपा के पक्ष में यह बात आती है कि पहले लोकसभा का चुनाव होना है, जो धनमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर होना है। इसलिए लोकसभा चुनाव में बिल्कुल निचले स्तर पर जातियों विभाजन होने की संभावना कम है। लेकिन विधानसभा चुनाव में तस्वीर पूरी तरह से बदल भी आकरती है। यह बात समझने की जरूरत है कि अगर

सत्ता के शीर्ष पर बैठा नेता अपनी जाति के बोट आकर्षित करता है तो उसकी बजह से दूसरी जातियों के बोटों में विकर्षण भी होता है। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि चुनाव से पहले जिसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है चुनाव जीतने के बाद भी वही सीएम बनता है। गुजरात से उत्तराखण्ड तक यह बात दिखाई देती है। उत्तराखण्ड में तो मुख्यमंत्री रहते विधानसभा का चुनाव हारने वाले पूछर सिंह धामी को ही सीएम बनाया गया था। इस हिसाब से हरियाणा के मतदाताओं में यह मैसेज अपने आप जाएगा कि भाजपा जीतेगी तो फिर सैनी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यह मैसेज विधानसभा चुनाव में कई जातियों को भाजपा से दूर भी कर सकता है। ध्यान रहे जमीनी स्तर पर जातियों की गोलबंदी हमेशा एक जैसे अंदाज में काम नहीं करती है। यह मानना भी पूरी तरह से ठीक नहीं होगा कि दुष्यंत चौटाला को अब भाजपा ने अपने से दूर कर दिया तो वे अलग लड़ कर जाट बोटों का बंटवारा कर देंगे, जो अभी लगभग पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने प्रदेश की कमान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को सौंपी है। वे 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जाट उनके साथ एकजुट हुए थे, जिससे कांग्रेस को 30 सीटें मिलीं। उस चुनाव में दुष्यंत चौटाला की नई बनी जननायक जनता पार्टी को 10 सीटें मिली थीं। चुनाव के बाद एक समय ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस और चौटाला की पार्टी मिल कर सरकार बना सकते हैं। लेकिन भाजपा को केंद्र और राज्य की सत्ता में होने का लाभ मिला और उसने चौटाला के साथ मिल कर सरकार बना ली। चौटाला चार साल से ज्यादा समय तक कई महत्वपूर्ण मंत्रालय लेकर उप मुख्यमंत्री बने रहे। इसलिए अचानक अलग होकर वे भाजपा विरोधी राजनीति करते हैं तब भी भाजपा विरोधी नेता की उनकी साख नहीं बनेगी। सो, उनके जरिए जाट बोटों का बंटवारा हो ऐसा भाजपा की सदिच्छा हो सकती है लेकिन यह इच्छा पूरी होगी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

हिमाचल में हलचल, हरियाणा में परिवर्तन

કુલદાપ ચદ આંગનહાત્રા

यदि कांग्रेस इन छह पूर्व विधायकों को फिर से शीकार लेती है, तो क्या होगा। राजनीति संभावनाओं में खेल है। अब कांग्रेस इनको पार्टी में तो बापस ले कर्ती है, लेकिन विधानसभा का अध्यक्ष अब इनको बारा विधानसभा का सदस्य नहीं बना सकेगे। अब लोकसभा के चुनाव परिणामों का इंतजार है भारतीय नता पार्टी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री बदल दिया है और आचल में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री सुखविंदर वंह सुक्खू को फिलहाल 'स्टेट्स को' दिया हुआ है। लिंगन सबसे ज्यादा आश्र्य मनोहर लाल खट्टर की गह नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर व्यक्त क्या जा रहा है। चार दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मनोहर लाल की जमकर तारीफ की और दूसरे ही उन उहोंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के तुरन्त बाद विधायक दल की बैठक हुई और उसमें मनोहर लाल नायब सिंह सैनी, जो फिलहाल हरियाणा भाजपा के अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, का नाम भाजपा विधायक दल के नए नेता के तौर पर पेश किया, जिसे वर्समति से स्वीकार किया गया। और उसके साथ ही ज्यपाल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी। गले दिन उहोंने विधानसभा में 48 विधायकों के मर्�थन से अपना बहुमत भी सिद्ध कर दिया। यह सारा टनाक्रम इतनी तेजी से घटित हुआ कि मीडिया इसकी नक तक नहीं पा सका। लेकिन इस आप्रेशन में, नायक पार्टी, जो ओमप्रकाश चौटाला के परिवार में जनीतिक कुशरी के चलते अस्तित्व में आई थी,

मी के पद पर विराजमान थे। नब्बे में भाजपा के 41 विधायक हैं। की सरकार को सात निर्दलीय दे दिया तो जननायक दुष्यन्त की ब जानते हैं कि राजनीति में बिना को नहीं ढोता। कहा जा रहा है कि लोकसभा की दस सीटों में से दो हैं थे, लेकिन भाजपा एक सीट देने वाले पांच साल में जननायक पार्टी ने दृग्मन्त चौटाला की कार्यप्रणाली के अंतर ओमप्रकाश चौटाला की पार्टी नैशनल लोकदल, अपनी तमाम वजूद हरियाणा में पुनः जड़े नहीं जनता पार्टी ने चौटाला परिवार के अन को देख लिया था, लेकिन उपर जानकर भी अनजान बना हुआ दुष्यन्त चौटाला तो अपनी शर्तों पर तक कि दुष्यन्त अपने ही घर में आवाज नहीं सुन सका। उसके दस च उसका साथ छोड़ गए। कुल नायक उसके पास बचे। भाजपा सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से मरसता का ऐतिहासिक प्रयोग कर क चलते नायब सिंह सैनी हरियाणा ओबीसी श्रेणी से आते हैं जिससे रा संदेश गया है। सोनिया कांग्रेस

के राहुल गांधी जब पूरे देश में धूम धूम कर यह घोषणा कर रहे हैं कि यदि वे प्रधानमंत्री बन गए तो वे भारतीय सामाजिक संरचना को राजनीति की बिसात पर ‘जाति जनगणना’ के नाम पर तार-तार करके रख देंगे, तब भारतीय जनता पार्टी ने बिना शोर-शराबा किए नायब सिंह को मुख्यमंत्री बना कर व्यावहारिक धरातल पर हरियाणा में एक नया प्रयोग किया है। इससे हुड़ा परिवार व चौटाला परिवार दोनों सकते में हैं। न निगलते बनता है, न उगलते बनता है। ऐसे समय जब सोनिया गांधी, भूपेन्द्र सिंह हुड़ा, ओम प्रकाश चौटाला, लालू यादव, अखिलेश यादव व एमके स्टालिन अपने परिवार से बाहर न देखने को तैयार हैं और न ही निकलने को तैयार हैं, नायब सिंह सैनी का मुख्यमंत्री बनना देश में परिवारवाद की राजनीति पर गहरा आघात है। राजनीति के धुर्धर पंडित भी भाजपा की इस सांगठनिक कुशलता पर सिर धुनते नजर आ रहे हैं। इससे पूर्व राजस्थान, मध्यप्रदेश व छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने नए मुख्यमंत्रियों के चयन के समय सबको चौंकाया था। राजनीतिक विश्लेषणों की शब्दावली में चाहे इसे चौंकाना कहा जाए, लेकिन यह भारतीय राजनीति में ऐसा प्रयोग कहा जा सकता है जो कई स्थापित मिथकों को तोड़ता है। कांग्रेस पार्टी ने जहां भारतीय जनतंत्र में परिवारवाद का वृक्ष रोपने की कोशिश की, जिसकी देखादेखी दूसरे राजनीतिक दलों में भी यह प्रदूषण फैला, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने उसी ‘जन’ को राजनीति के केन्द्र में स्थापित करने की कोशिश की जिसके बलबूते ‘जनतन्त्र’ चलता है। हरियाणा में मनोहर लाल से नायब सैनी तक के इस

स्वर्गिक हेती, नरक में धंसता

श्रुति व्यास

हेती ये नाम जादू की दुनिया के किसी देश का गता है। हेती को खोजने के लिए हमें क्रिस्टोफर लेलंबस का शुक्रगुज़ार होना चाहिए। हेती में वह सब छ है जिसके लिए दुनिया का कैरीबियन क्षेत्र जाना चाहता है झुंगु खुशनुमा ट्रॉपिकल मौसम, हरियाली, झरने, एक नीला पानी और वह सब जो आपको प्रसन्नता देंगे शांति दे सकता है। मगर परियों की कहानियां हमें जाती हैं कि जादू की दुनिया पर हमेशा किसी दुष्क्रांत की बुरी नजर लगी रहती है। हेती पर भी है। यह लगातार राजनैतिक अस्थिरता और प्राकृतिक प्रदारों का शिकार बनता रहा है। फॉस के इस पूर्व निवेश के निवासी सुख-चैन से जीना जान ही नहीं ए है। द्वालिए की तानाशाही के अवसान के बाद के छले 38 सालों में हेती के लोगों ने 19 शासक देखा हैं। देश में कानून-व्यवस्था का नामेनिशन नहीं और लोगों की जिद्दी और रोज़ी-रोटी हमेशा खतरे रहती है। बलात्कार, हत्याएं और चोरियां आम हैं। रीब 1.15 करोड़ की आबादी वाले इस देश का लाना बजट 2.2 अरब अमरीकी डॉलर है। जुलाई 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपित जोवेनल मोईस की उनके अधिकारिक निवास में हत्या कर दी गई थी। तब से यां में राजनैतिक अराजकता का माहौल और गहरा गा है। देश की आधी आबादी झुंग करीब 55 लाख झुंगों मानवीय सहायता की ज़रूरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ के नुसार, हेती में करीब 10 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। इनमें से जो बच्चे आपराधिक गिरोहों के लिए वाले इलाकों में रहते हैं, वे इन गिरोहों में अमिल हो रहे हैं। कोढ़ में खाज यह कि 2022 में हेती है जा एक महामारी के रूप में फैल जिससे देश की



कमर टूट गयी। और अब हेती एक नयी मुसीबत में है। वह गृहयुद्ध की कागर पर है। गत 7 मार्च से अपराधियों के गिरोह देश की राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस की सड़कों पर उत्पात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी का करीब 80 प्रतिशत हिस्सा उनके कब्जे में है। प्रधानमंत्री एरियल हेनरी देश में नहीं हैं, जहाँ वे उस देश द्वारा 1,000 पुलिसकर्मी हेती भेजे जाने के लिए समझौते पर दस्तखत करने गए थे। हेनरी ने केन्या से यह सहायता 2022 में मार्गी थी और 2023 में संयुक्त राष्ट्रसंघ ने उनकी मांग का अनुमोदन किया। हेनरी की अनुपस्थिति गँगों के लिए राजधानी पर कब्जा करने का सुनहरा मौका बन गयी है। वे सरकारी इमारतों पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने देश के सभी 4,000 जेलों के दरवाजे खोल दिए हैं और सारे के सारे कैदी भाग निकले हैं। उन्होंने हवाईअड्डों और पुलिस थानों को घेर रखा है। कुल मिलाकर, वहां भारी अफरातफरी और अराजकता का माहौल है। एरियल हेनरी वापस अपने देश नहीं आ पा रहे हैं। हेती की पुलिस और सेना

A wide-angle photograph capturing a large, diverse crowd of people, likely at a public event or protest. In the center-left, two young boys in white school uniforms are prominently featured, each holding one end of a large flag. The flag has three horizontal stripes: blue on top, red in the middle, and yellow on the bottom. To the left of the boys, a police officer wearing a grey helmet and a dark uniform is visible, standing on a raised platform. The background is filled with many other individuals, mostly young people, some wearing hats and casual clothing. The scene appears to be set in an urban environment with buildings visible in the distance under a clear sky.

लाचार है। गैंगों के गुणों की संख्या उनसे कहीं ज्यादा है और कई मामलों में सैनिक और पुलिसकर्मी गोलावारी में भी गैंगों के आगे टिक नहीं पा रहे हैं। गैंगों की एक ही मांग है झ़ प्रधामंत्री एरियल हेनरी इस्टीफा दें। जिमी चेरिजेर, जिन्हें 'बारेक्स' के नाम से जाना जाता है, गुंडों की इस विशाल फौज के मुखिया हैं। उन्होंने पोर्ट ओ प्रिंस में संवाददाताओं को बताया कि अगर एरियल हेनरी इस्टीफा नहीं देते तो देश में गृहयुद्ध और कल्पेआम होगा। लाचार एरियल हेनरी ने इस्टीफा दे दिया है। ये गैंगें अचानक क्यों मैदान में कूद पड़ीं और पहले से बर्बाद देश को और बर्बाद करने में क्यों जुट गईं? बात यह है कि उन्हें लग रहा था कि वे खतरे में हैं। इन गैंगों के मुखिया माफिया हैं, डॉन हैं। वे जमीनें, होटलों, घरों और यहाँ तक कि परचूनी की दुकानों और पेट्रोल पम्पों के मालिक हैं। अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को हेती में कुछ भी करना है तो उन्हें इन गैंगों की कृपादृष्टि चाहिए ही होती है। अब तक संयुक्त राष्ट्र हेती को धन उपलब्ध करवाता रहा है और

संक्षिप्त समाचार

**गढ़चिरौली के जंगलों में
नक्सल से मुठभेड़**

बीजापुर/सुकमा(विश्व परिवार)। लोकसभा चुनाव से पहले नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। बस्तर संभाग में लगातार हमले के बाद अब नक्सलियों का मूँहमेंट महाराष्ट्र सीमा में दर्ज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर कोलामार्का के जंगलों में सुशक्षणालों ने नक्सलियों के मसूबों पर पानी फेर दिया। दरअसल, छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से हमले में 36 लाख के चार इनापी नक्सली मारे गए। हालांकि, सर्विंग के बाद जवानों ने घोके से एक 47 समेत कई व्यवस्थाएँ बरामद किया है। यह मुठभेड़ गढ़चिरौली के कोलामार्का के जंगलों में हुई है। दरअसल, गढ़चिरौली पुलिस को छत्तीसगढ़-महाराष्ट्र सीमा पर कोलामार्का के जंगलों में बड़े नक्सलियों की पौजूदी की खबर मिली। इस पर जवानों ने नक्सलियों को घोके से सर्विंग अधिभान शुरू किया। सी-60 कमांडो को कोलामार्का के जंगलों में नक्सलियों को घोके लिया। नक्सलियों ने अपने आप को घिरा पाकर जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सी-60 कमांडो के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मुहातोड़ जवाब दिया। सी-60 कमांडो के जवानों ने मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चार नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में नक्सली डीवीसी में बरामार्का, डीवीसी मंगतू, प्लाटून सदस्य कुरसम राजू और प्लाटून सदस्य बैंकेट्स मारे गए। ये सभी माओवादी तेलगुना राज्य समिति के सदस्य थे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली बैंकर्स की बैठक

बालोद(विश्व परिवार)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री इन्द्रजीत सिंह चंद्रवाला ने लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के महेन्जर बालोद जिले के बैंकर्स की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उहोंने कहा कि निर्वाचन कार्य के सफल संपादन में बैंकर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। श्री चंद्रवाला ने कहा कि बैंकर्स लोकसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खाता अपनी शाखाओं में प्राथमिकता के साथ खुलाए। उहोंने बैंकर्स को लोकसभा आम निर्वाचन के दौरान खाताधारकों के खाते में सामान्य लेन-देन में अचानक बढ़िया होने पर उपका पूरी गंभीरता से निगरानी करने के निर्देश दिए। श्री चंद्रवाला ने बैंकर्स को आवश्यकतानुसार अपने शाखा में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खाते जीरो बैंकेंस में खालने एवं प्रत्याशियों के बैंकिंग कार्य को प्राथमिकता के साथ करने के निर्देश दिए। इसके लिए उहोंने जरूरत पड़ने पर पुष्टक से कांटर बनाने के निर्देश भी दिए। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री चंद्रवाला के बैंकर्स की बैठक निर्वाचन कार्य के अंतर्गत बैंकर्स की ड्यूटी माहितो आज्ञावर के रूप में लगाई जाएगी। इसके लिए उहोंने बैंक अधिकारियों को जानकारी भी देने को कहा। बैठक में संयुक्त कलेक्टर एवं व्यव अनुवीक्षण के नोडल अधिकारी श्रीमती पूजा बसल सहित अन्य अधिकारी

जल जीवन मिशन से पानी की सुविधा नहीं, सलोरा क्षेत्र के लोग परेशान

कोरबा(विश्व परिवार)। कट्टोरा विकासखंड के सलोरा क्षेत्र में इस गर्मी में लोग हैरान हैं कि उहोंने जल जीवन मिशन का पानी कब मिलाया। लोक स्वास्थ्य व्यांकियों की विभाग ने योजना कि क्रियान्वयन कराया जा रहा है। ग्रामीण बताते हैं कि टेरेस्ट्रिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर सलोरा गांव में 500 के आसपास घर हैं जहां पर जल जीवन मिशन से उच्च और शुद्ध पेयजल उपलब्ध करने का मायदा तैयार किया गया। पाइप लाइन बिछाने के साथ नल कनेक्शन दे दिए गए, दूसरी व्यवस्थाएँ भी पूरी कर ली गईं। इन लोगों को जानने की कोशिश की गयी और योजना का नियांवन्यन ठेकेदार करना किया गया। योजना को पूर्ण हुए असरों का बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नतीजे दूर हैं। मार्डिया से जुड़े लोगों ने आज यहां का जायजा लिया। स्थानीय लोगों से बातचीत को गई और योजना को जानने की कोशिश की। गर्मीओं ने अप्सोरों के प्रबंधन और जानकारियों को नियांवन्यन ठेकेदार करने के लिए रुट चार्ट को गमान की जायजा किया। योजना को पूर्ण हुए असरों को बोलबाला हो चुका है लेकिन नत

